IJIRSET
International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2347-6710

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 11, Issue 6, June 2022

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 8.118

9940 572 462 6381 907 438 ijirset@gmail.com www.ijirset.com

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET)

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 6, June 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1106137|

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की मोदी योजना को मिली नई उड़ान

Dr. Mamta Singh

Assistant Professor in Political Science, Government College, Maniya, Dholpur, India

सार

नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने कई चुनौतियां थीं. लेकिन पिछले आठ साल के दौरान सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की. जिससे सरकार की लोकप्रियता काफी बढ़ गई, आज कई सफल योजनाओं की चर्चा घर-घर में होती हैं. केंद्र में मोदी सरकार के आठ साल पूरे हो गए हैं. मोदी सरकार 2.0 की तीसरी सालगिरह 26 मई को है. बीजेपी साल-2014 के मुकाबले 2019 में और बड़ी जीत के साथ सत्ता में लौटी. इस बड़ी जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शुरू की गईं तमाम कल्याणकारी योजनाओं ने अहम भूमिका निभाईं. हालांकि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने कई चुनौतियां थीं. सरकार के इस आठ साल के सफर में कुछ योजनाएं बेहद लोकप्रिय रही हैं. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 6.1 लाख लाभार्थियों को करीब 2691 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता राशि जारी करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विकास की योजनाओं को तेज गति से अमली जामा पहनाने और अपराधियों व दंगाइयों पर सख्ती के लिए योगी सरकार की जमकर सराहना की। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर योजना के लाखों लाभार्थियों के लिए वित्तीय सहायता जारी की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने योजना के लाभार्थियों से संवाद भी किया और उन्हें नये मकान की शुभकामनाएं भी दी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2016 में शुरु हुई इस योजना ने देश के गांव की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है और उनकी सरकार की कोशिश है कि मूलभूत सुविधाओं में गांव और शहर के बीच का अंतर कम किया जा सके।

परिचय

उन्होंने कहा, "गांव में सामान्य व्यक्ति के लिए भी जीवन उतना ही आसान हो जितना बड़े शहरों में है। प्रधानमंत्री आवास योजना को शौचालय, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी जोड़ा जा रहा है।" उन्होंने कहा कि बीते चार वर्षों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं को जिस तेजी से आगे बढ़ाया है, उससे राज्य को एक नई पहचान भी मिली है और नई उड़ान भी मिली है। उन्होंने कहा, "एक तरफ अपराधियों और दंगाइयों पर सख्ती और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था पर नियंत्रण। एक तरफ अनेक एक्सप्रेस वे का तेजी से चल रहा काम, तो दूसरी तरफ एम्स जैसे बड़े संस्थान। मेरठ एक्सप्रेस वे से लेकर बुंदेलखंड गंगा एक्सप्रेस वे तक उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज करेंगे।" प्रधानमंत्री ने कहा कि यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में बड़ी-बड़ी कंपनियां भी आ रही हैं और छोटे छोटे उद्योगों के लिए भी रास्ते खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन में हीला-हवाली के लिए उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती समाजवादी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मोदी ने कहा कि पहले गरीबों को यह विश्वास ही नहीं था कि सरकार भी घर बनाने में उसकी मदद कर सकती है। उन्होंने कहा, "जो पहले की आवास योजनाएं थीं और उसके तहत जिस स्तर के घर बनाए जाते थे, वह भी किसी से छिपा नहीं है। गलती गलत नीतियों की थी लेकिन नियति के नाम पर गरीबों को भुगतना पड़ता था।" उन्होंने कहा, "मुझे याद है 2016 में हमने जब इस योजना की शुरूआत की थी तो कितनी परेशानी आई थी। पहले जो सरकार थी उसे कितनी ही बार भारत सरकार की तरफ से चिट्ठियां लिखी गई थी। लेकिन वह इसे नजरअंदाज करती रही। उस सरकार को आज भी उत्तर प्रदेश का गरीब भुला नहीं है।"

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 6, June 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1106137|

उन्होंने कहा कि आज योगी आदित्यनाथ की सरकार की वजह से यहां आवास योजना के काम की गति भी बदल गई और तरीका भी बदल गया है। उन्होंने कहा, "आज उत्तर प्रदेश में करीब 22 लाख ग्रामीण आवास बनाए जाने हैं। इनमें से 21.5 लाख घरों को बनाए जाने की स्वीकृति भी दी जा चुकी है।" प्रधानमंत्री द्वारा बुधवार को जारी वित्तीय सहायता में 5.30 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त और 80 हजार लाभार्थियों को जारी दूसरी किस्त शामिल है। ये 80 हजार लाभार्थी पहली किस्त का लाभ ले चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक सभी के लिए पक्के मकान का आह्वान किया था। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। अब तक इस योजना के तहत देश भर में 1.26 करोड मकान बनाए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लोगों को खुद का पक्का घर बनाने के लिए तथा पुराने घर की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। समतल भूमि पर पक्का घर बनाने के लिए केंद्र सरकार 1,20, 000 रुपये की आर्थिक सहायता जबकि पहाड़ी इलाकों में पक्के घर के निर्माण के लिए 1,30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि के अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत अकुशल श्रमिक की मजदूरी के रूप में सहायता और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण या किसी अन्य स्रोत से शौचालय के निर्माण के लिए 12 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती है। इस योजना में भारत सरकार, राज्य सरकार तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के कई कार्यक्रमों और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है।[1,2]

नागर विमानन मंत्रालय(ministry of civil aviation) ने भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को ड्रोन के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। इसकी सहायता से 100 जिलों के कृषि क्षेत्र में रिमोट से सैमसंग डाटा एकत्र किया जाएगा। इससे ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उपज अनुमान के लिए एकत्रित किया जाएगा। ड्रोन के इस्तेमाल से फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन और उनके बारे में सटीक जानकारी जुटाई जा सकेगी।

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 6, June 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1106137|

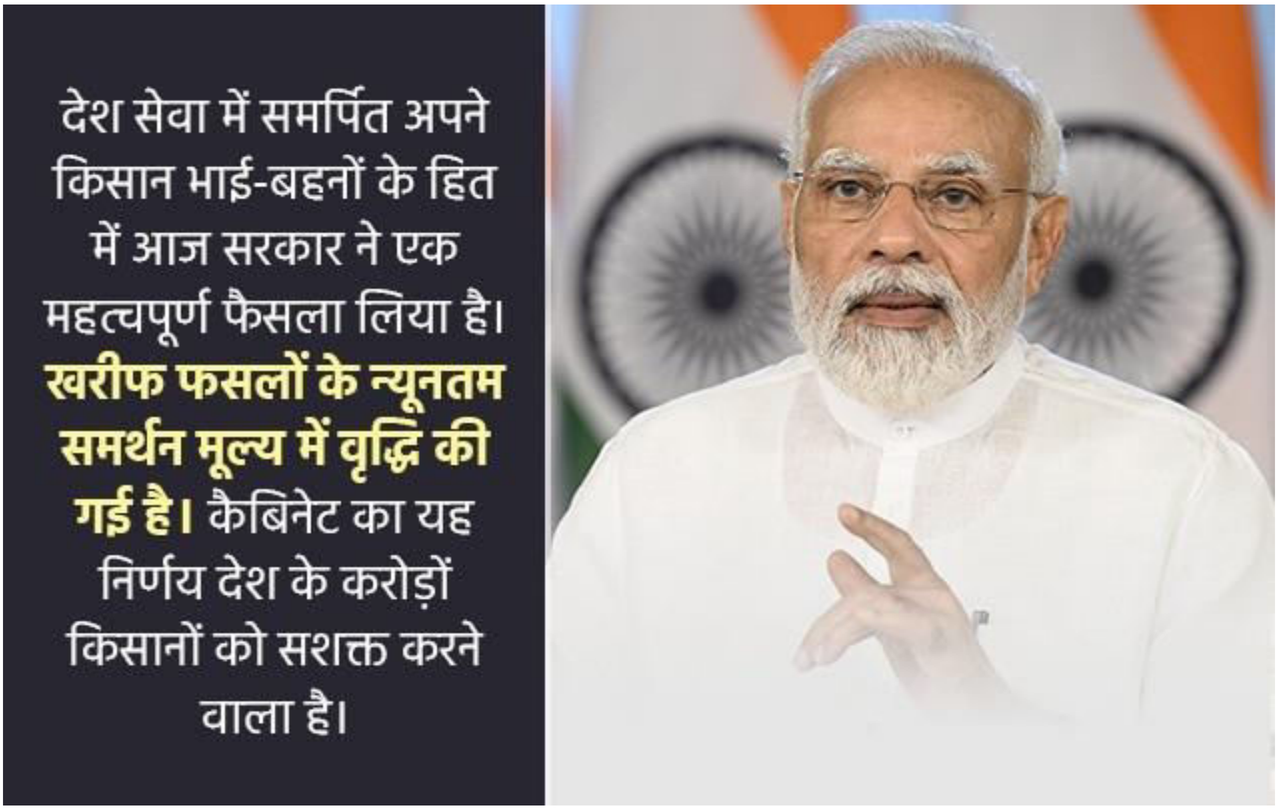

इससे फसलों में सुधार और पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगर नीतियां सही हों तो देश कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है। आज का दिवस इसका बड़ा उदाहरण है। कुछ साल पहले तक देश में जब ड्रोन का नाम लिया जाता था, तो लगता था कि ये सेना से जुड़ी हुई कोई व्यवस्था है। ये दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए उपयोग में आने वाली चीजें हैं। उसी दायरे में सोचा जाता था। लेकिन आज हम मानेसर में किसान ड्रोन सुविधाओं का उदाहरण कर रहे हैं। ये 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। मुझे विश्वास है ये शुरूआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी बल्कि इसमें संभावनाओं का एक अनं्त आकाश भी खुलेगा। मुझे भी बताया गया है, कि गरुड़ एयरोस्पेस ने अगले दो वर्षों में एक लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे अनेकों युवाओं को नए रोजगार और नए अवसर मिलेंगे। मैं इसके लिए गरुड़ एयरोस्पेस की टीम को, सारे नौजवान साथियों को बधाई देता हूं।[3,4]

आजादी का अमृतकाल है मोदी ने कहा- देश के लिए ये समय आजादी के अमृत काल का समय है। ये युवा भारत का समय है और भारत के युवाओं का समय है। पिछले कुछ वर्षों में देश में जो reforms हुए हैं। युवाओं और प्राइवेट सेक्टर को एक नई ताकत दी है। ड्रोन को लेकर भी भारत ने आशंकाओं में समय नहीं गंवाया। हमने युवा टैलेंट पर भरोसा किया और नई सोच के साथ आगे बढ़े। इस बार के बजट में हुई घोषणाओं से लेकर अन्य नीतिगत फैसलों में देश ने खुलकर टेक्नोलोजी और इनोवेशन को प्राथमिकता दी है। इसका परिणाम आज हमारे सामने हैं। वर्तमान में ही हम देख रहे हैं कि ड्रोन का कितना विविध इस्तेमाल होने लगा है। अभी बीटिंग रिट्रीट के दौरान एक हजार ड्रोन्स का शानदार प्रदर्शन पूरे देश ने देखा।
आज स्वामित्व योजना के तहत गांव में ड्रोन के जरिये जमीन का, घरों का हिसाब किताब तैयार हो रहा है। ड्रोन के जरिये दवाओं की सप्लाई हो रही है। मुश्किल इलाकों में वैक्सीन पहुंच रही हैं। कई जगह खेतों में दवाओं का छिड़काव भी ड्रोन से शुरू हो गया है। किसान ड्रोन अब इस दिशा में एक new age revolution की शुरूआत है। उदाहरण के तौर पर आने वाले समय में हाई कैपेसीटी ड्रोन की मदद से किसान अपने खेतों से ताजी सब्जियां, फल, फूल बाजार भेज सकते हैं। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी और समंदर से सीधे ताजी मछलियां बाजार भेज सकते हैं। कम समय मिनिमल डेमेज के साथ मछुारों का, किसानों को सामान बाजार पहुंचेगा तो उनकी मेरे किसान भाईयों की मेरे मछुआरे भाई -बहनों की, उनकी आय भी बढ़ेगी। ऐसी अनेक संभावनाएं हमारे सामने दस्तक दे रही हैं।[4,5]

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 6, June 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1106137|

मुझे खुशी है...
मुझे खुशी है कि देश में कई और कंपनीयां इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। भारत में ड्रोन स्टॉर्ट-अप्स का एक नया इको सिस्टम तैयार हो रहा है। अभी देश में 200 से ज्यादा ड्रोन स्टार्ट-अप काम कर रहे हैं। बहुत जल्द ही इनकी संख्या हजारों में पहुंच जाएगी। इससे रोजगार के भी लाखों नए अवसर खुलेंगे। मुझे विश्वास है आने वाले समय में भारत का ये बढ़ता सामर्थ्य पूरी दुनिया को ड्रोन के क्षेत्र में नया नेतृत्व देगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत - बहुत धन्यवाद, मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं। नौजवानों के साहस को मेरी शुभकामनाएं हैं। आज जो स्टार्ट-अप की दुनिया खड़ी हुई है। ये जो नौजवान साहस कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। उसको मैं बहुत - बहुत बधाई देता हूं। और भारत सरकार नीतियों के द्वारा लगातार आपके साथ रहकर के, कंधे से कंधा मिलाकर के आपको आगे बढ़ने में कोई रूकावट नहीं आने देगा।
दिसंबर, 2021 में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर(Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) ने फसल की सुरक्षा के लिए कीटनाशक के प्रयोग तथा मिट्टी एवं फसल के पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन के इस्तेमाल हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की थी। इसका उद्देश्य इस साल में किसान की आय को दोगुना करना है। बता दें कि देश के विभिन्न राज्यों में टिड्डियों के हमलों को रोकने के लिए पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। [6,7]

ड्रोन नियम 2021 बनने के बाद अब इसका इस्तेमाल कृषि के कई क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे फसल के दबाव की निगरानी, पौधों की वृद्धि, पैदावार की भविष्यवाणी, खरपतवार नाशक, उर्वरक तथा पानी जैसी सामग्रियों का वितरण करना। किसी भी वनस्पति या फसल के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है, खरपतवार, संक्रमण तथा कीटों से प्रभावित क्षेत्र और इस आकलन के आधार पर, इन संक्रमणों से लड़ने के लिए आवश्यक रसायनों का सटीक मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे किसान की कुल लागतमें काफी कमी की जा सकती है। कई स्टार्ट-अप्स द्वारा ड्रोन प्लांटिंग सिस्टम भी विकसित किए गए हैं, जो ड्रोन को पॉड्स, उनके बीजों को शूट करने तथा मिट्टी में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को स्प्रे करने की सुविधा देते हैं। इस प्रकार, यह तकनीक लागत को कम करने के अलावा फसल प्रबंधन की निरंतरता और दक्षता को बढ़ाती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 18 फरवरी, 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की शुरूआत की घोषणा के 6 वर्ष पूरा होने के बाद इस योजना ने आगामी खरीफ 2022 सीज़न के साथ अपने कार्यान्वयन के 7वें वर्ष में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। पीएमएफबीवाई भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल के नुकसान/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पीएमएफबीवाई के तहत 36 करोड़ से अधिक किसानों का बीमा किया गया है। 4 फरवरी, 2022 तक इस योजना के तहत 1,07,059 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है।

विचार-विमर्श

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को महत्वाकांक्षी 'उड़ान' योजना (उड़े देश के आम नागरिक) की शुरूआत की। पीएम मोदी ने शिमला के एयरपोर्ट जुबरहट्टी तीन उड़ानों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके बाद इकडप्पा-हैदराबाद, शिमला-दिल्ली, नांदेड़-हैदराबाद सस्ती हवाई सेवा शुरू की गई है।

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 6, June 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1106137|

पीएम ने अपने संबोधन में हवाई सफर के सस्ता किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हवाई सफर अब इतना सस्ता हो जाएगा कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी इसका लाभ उठा पाएंगे। पीएम ने कहा कि ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि हमारी पहली सरकार है जो देश में एवीएशन पॉलिसी ला रही है। नई पॉलिसी के तहत हवाई यात्रा का खर्चा सिर्फ 6 या 7 रुपये किलोमीटर हो जाएगा। गौरतलब है कि इस योजना का उद्देश्य छोटे शहरों के आम नागरिकों को सस्ते दर पर हवाई सेवाएं मुहैया कराना है। इस बीच पीएम बोले की नांदेड़-अमृतसर-पटना साहेब के बीच विमान सेवा का रुट बने। विमान सफर इस पॉलिसी के बाद टैक्सी के सफर से भी सस्ता हो जाएगा। पीएम ने कहा कि देश में कई हवाई पट्टियां हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। एविएशन विभाग को बधाई देते हुए पीएम ने कहा कि इस महत्वकांशी योजना का आरंभ हो रही है, जो बहुत कम समय में देश के लोगों को बड़े स्तर पर जोड़ेगी। गौरतलब है कि इस योजना की घोषणा पिछले साल अक्टूबर में नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजापति राजू और राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने की थी। उन्होंने कहा थी कि इस योजना का मकसद क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा था कि यह दुनिया में सस्ते हवाई किराए को लेकर अपनी तरह की पहली स्कीम है। हालांकि जनवरी में ही इस सेवा के शुरू होने की उम्मीद थी।[8,9]

1. उड़ान योजना को अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया था। ये राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (एनसीएपी) की एक प्रमुख योजना है।

2. इस योजना के तहत आम नागरिक न्यूनतम 2500 रुपये में एक घंटे का सफर तय कर सकते हैं।

3. सरकार की इस यजना का उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देना है। ये अपने आप का ऐसी पहली योजना है।

4. इस योजना में सरकार का मकसद ऐसी 45 हवाई अड्डों को जोड़ने का है जहां कम फ्लाइट्स उड़ान भरती है।

5. इस योजना का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला के एयरपोर्ट जुबरहट्टी से करेंगे।

6. ट्वीट्स के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये जानकारी दी है कि इस योजना में 500 किलोमीटर की एक घंटे की यात्रा में न्यूनतम 2,500 रुपया किराया देना होगा।

7. लंबे मार्गों और उड़ान अवधि के दौरान किराए में बदलाव हो सकता है।

8. एक व्यक्ति एक फ्लाइट में करीब 6 से 40 सीटें बुक करवा सकता है।

9. एयरलाइंस केवल 50 फीसदी टिकट को सस्ते दामों पर बेचेंगे। बाकि के टिकट बाजार मूल्य पर ही बेचे जाएंगे।

10. इस योजना के अंतर्गत, पांच कंपनियां 128 रूटों पर उड़ान सेवाएं संचालित करेगी जो पूरे देश में 70 हवाईअड्डों

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 6, June 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1106137|

से जुड़ेंगी। ऑपरेटरों में स्पाइसजेट, एयर ओडिशा, एयर इंडिया की सहायक कंपनी एयरलाइन सर्विसेज, एयर डेक्कन, और टर्बो मेघा शामिल होंगे।

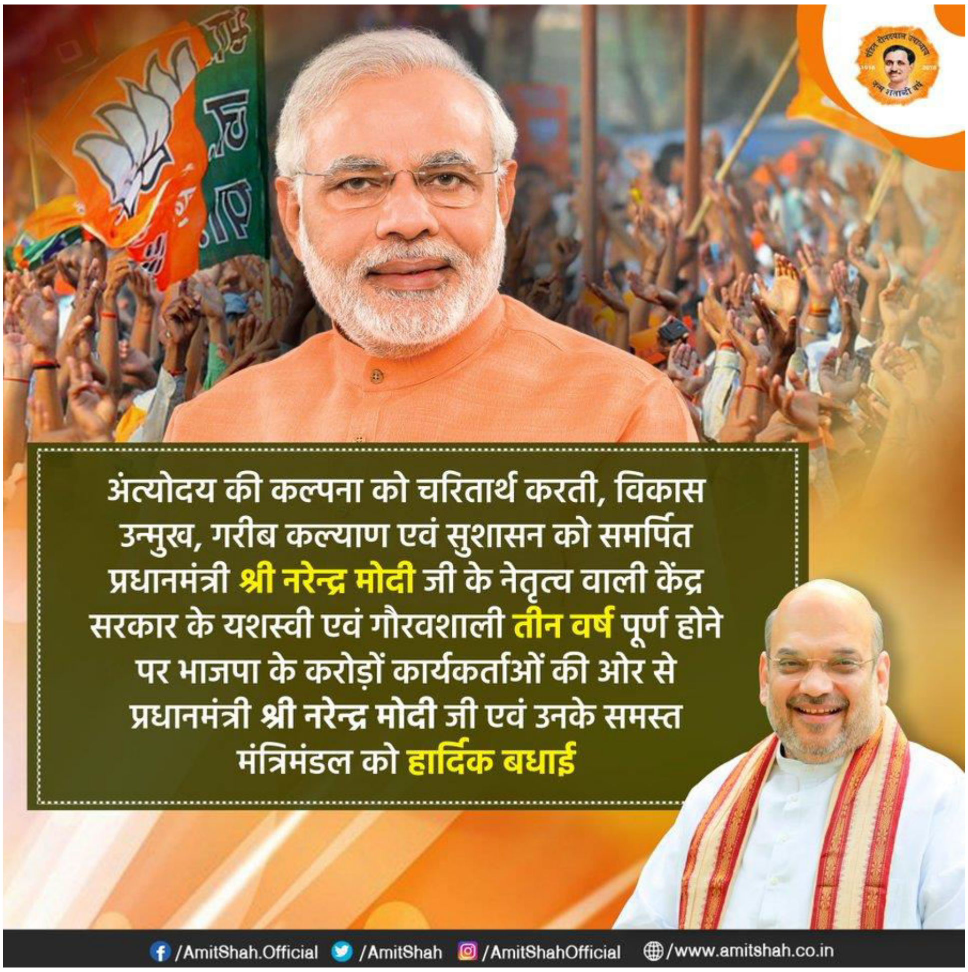

परिवहन के साधनों की गति जैसे-जैसे बढ़ती गई, वैसे-वैसे वैश्विक प्रगति उस पर निर्भर होती गई। पिछली लगभग दो शताब्दियों के मशीनी युग यानी 'औद्योगिक क्रांति' का इतिहास देखें तो रेल, सड़कों पर चलने वाले तमाम वाहन और समुद्री जहाज से लेकर विमान आदि की गति को तकनीक की मदद से बढ़ाने में व्यापक तौर पर मदद मिली है। यह भी कह सकते हैं कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से इनकी स्पीड में वृद्धि संभव हुई। साथ ही तकनीक के विकास से इनकी क्षमताओं का निरंतर विस्तार होता गया। नए नए आविष्कारों की मदद से नई तकनीकें आती गईं और 'हाइ स्पीड' के नए कीर्तिमान स्थापित होते गए। 'हाइ स्पीड' की मदद से केवल यातायात और उससे संबंधित अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि मानव संसाधन के क्षेत्र में भी वृद्धि होती है। इन परिस्थितियों के बीच यह स्वाभाविक है कि विकसित देश अपने महत्वपूर्ण शहरों के बीच की रेल सेवाओं को हाई स्पीड से जोड़ना चाहते हैं।[10,11]

इस संदर्भ में यदि हम भारत की बात करें तो यह सही है कि पिछले लगभग पांच-छह दशकों में भारतीय रेल की औसत गति (कुछ चुनिंदा ट्रेनों और रूट को छोड़कर) को बहुत अधिक बढ़ाने में सफलता नहीं मिली है। बीते दिनों प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 'गति शक्ति' योजना से इस दिशा में व्यापक सफलता मिलने की उम्मीद जगी है। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के दौर में इस योजना के माध्यम से देश की आधारभूत संरचना का सर्वांगीण विकास करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत पहले से मौजूद आधारभूत संरचना के आधुनिकीकरण के साथ ही नए बुनियादी ढांचों का निर्माण करने के लिए समग्र व युक्तिसंगत तरीका अपनाया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से उद्योगों की गति को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।

हालांकि इस दिशा में एकीकृत रूप से आगे बढ़ने के लिए वर्तमान में परिवहन के विविध साधनों में आपसी तालमेल का अभाव दिखता है। इस योजना के माध्यम से इस गतिरोध को भी समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल इस योजना के तहत

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 6, June 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1106137|

भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क भूमि बंदरगाह, उड़ान आदि विभिन्न मंत्रलयों की महत्वाकांक्षी योजनाओं को एकीकृत किया जा रहा है। केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रलयों एवं राज्य सरकारों को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे देश के सभी क्षेत्रों तक पहुंचने में गुणवत्तापूर्ण सुधार की उम्मीद की जा रही है जिसका लाभ दीर्घकाल में देश की समग्र अर्थव्यवस्था को होगा।[12]

भारतीय रेलवे पहले ही 'गति शक्ति' के लिए रेलवे बोर्ड में एक विशेष निदेशालय का गठन कर चुका है। इस योजना का मूलभूत आधार इसरो की मदद से बीआइएसएजी-एन (भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फार स्पेस एप्लिकेशन एंड जियोइनफारमैटिक्स) द्वारा विकसित विशेष मानचित्र है। विकसित देशों में रेल लाइन बिछाने के अलावा परिवहन संबंधी आधारभूत ढांचा विकसित करने में इस तरह की तकनीक का उपयोग किया जाता रहा है। नदियों पर बनाए जाने वाले पुलों समेत पहाड़ी इलाकों में सुरंग आदि का एलाइनमेंट सेट करने में इसकी विशेष रूप से मदद ली जाती है। इससे निर्माण परियोजनाओं की प्रगति में काफी सुधार हुआ है।

वैसे एक तथ्य यह भी सही है कि बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं संसाधनों और संबंधित विभागों के बीच समन्वय पर निर्भर हैं। इस लिहाज से यह भी देखना होगा कि भारत में गति शक्ति योजना से संबंधित तमाम विभागों के बीच किस स्तर पर समन्वय हो पाता है, ताकि इसे धरातल पर उतारने में विशेष परेशानी सामने नहीं आए। इस योजना में भारतीय रेल की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का रेल का इतिहास बहुत पुराना और प्रमुख है।

किसी देश का उत्थान पेचीदा होता है, यह सिर्फ 'सुर्खियों' की रील नहीं होती. बड़ी घटनाओं के अलावा यह वैश्विक संदर्भ में घटनाओं, नेतृत्व वगैरह को साथ जोडने की प्रक्रिया है. बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आठ साल भारत के उत्थान महत्वपूर्ण दौर हैं- ऐसे 'न्यू' इंडिया का, जो महत्वाकांक्षी उम्मीदों से लबरेज है और जहां आत्म-विश्वास खिताब की तरह धारण किया जाता है.

आजादी के बाद, लुई माउंटबेटन की गवर्नर जनरल पद पर नियुक्ति से शुरू होकर प्रशासन और राजनीति में निरंतरता रही है. नेतृत्व निर्विवाद रूप से कांग्रेस के हाथ में रहा. जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद सरकार के शिकंजे देश और लोगों पर कस गए और 1947 का वह जोशो-खरोश जाता रहा. यह शिकंजा इमरजेंसी ले आया और हमें राहत जयप्रकाश नारायण और 1977 में जनता पार्टी की जीत की वजह से मिली. राजीव गांधी ने लाइसेंस राज को खोलना शुरू किया, लेकिन असली क्रांतिकारी बदलाव पी.वी. नरसिंह राव के तहत आया. निजी उद्यमियों के जज्बे को उड़ान का मौका मिला और भारत सरकारी शिकंजे से निकलना शुरू हुआ. राव की विरासत मोटे तौर पर बाजार संचालित अर्थव्यवस्था है, जिसके अपने नफा-नुकसान हैं. 1947 में राजनैतिक आजादी मिली तो राव के सुधारों ने अर्थव्यवस्था को खोला.

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET)

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 6, June 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1106137|

मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने. कोविड-19 जैसी महामारी की भयावह चुनौती के बावजूद उनके आठ साल में जन धन खाते, आयुष्मान भारत (राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना) जैसी गेम चेंजिंग योजनाएं दिखीं. सुर्खियों से अलग शायद सबसे अहम यह है कि मोदी के आठ साल भारत के उत्थान में निर्णायक मंच साबित हुए. भारत और भारतीयों ने 'आगे कदम बढ़ाया' और खुद में भरोसा बढ़ गया. मोदी-पूर्व भारत यथास्थिति को कबूल कर बैठा था यानी हिंदू प्रगति दर, गांवों में गरीबी, बार-बार प्राकृतिक आपदाओं में भारी जन हानि. हम लगातार घटनाओं से नियंत्रित होते रहे और 'माई-बाप सरकार' पर ज्यादा ही आश्रित थे. मोदी के तहत यह बदल गया और अति-सक्रियता और पूर्वाकलन का दौर शुरू हो गया.

कोविड से निबटना मिसाल बना. पहला लॉकडाउन का आदेश दिया गया, जबकि कई देश अभी दुविधा में फंसे थे. हालांकि अनेक लोगों, खासकर प्रवासी मजदूरों ने काफी तकलीफें उठाईं, लेकिन लाखों जानें बचाई जा सकीं. फिर टीकाकरण मुहिम शुरू हुई. विकसित देश टीकाकरण नीति के ब्यौरों पर बहस करते रहे, भात में 194 करोड़ से ज्यादा टीका लगाए गए. इसका एक नजरिया पेश करें तो यह भारत के बाद 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों की जनसंख्या के योग के बराबर है.

रक्षा क्षेत्र में भी अति सक्रियता जाहिर है. हमारी दुखती रग लंबी-प्रक्रिया वाली खरीद प्रक्रिया और तालमेल है. मोदी ने बिपिन रावत को पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ (सीडीएस) नियुक्त किया. जनरल रावत की मौत के पहले खरीद प्रक्रिया को दुरुस्त करने और सेना के तीनों अंगों में तालमेल में काफी सुधार हुआ. कश्मीर राज्य के लोगों देश की प्रगति से बाहर रहने का एक कृत्रिम भाव तकलीफदेह मुद्दा था. जैसे अलेक्जेंडर ने गॉर्डन नॉट काट डाली, अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया. निहितस्वार्थ हिंसा सहित हर कुछ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जम्मू-कश्मीर का भारत से जुड़ाव अब अपरिवर्तनीय है. मोदी ने यह आस्था भरी कि हम पक्के तौर पर अपनी तकदीर के स्वामी हो सकते हैं.

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 6, June 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1106137|

ऊंची उम्मीदें भी राजनैतिक नेतृत्व को घेर लेती हैं. महेंद्र सिंह धोनी के उभार ने बड़े शहरों से बाहर क्रिकेट का प्रसार संभव बनाया. इसका संकेत आइपीएल में बड़ी संख्या में प्रतिभाओं की आमद से मिलता है. मोदी राजनैतिक नेतृत्व को शहरी-एलीट वर्ग से बाहर ले आए. हालांकि चंद्रशेखर, एच.डी. देवेगौड़ा और चरण सिंह जैसे गैर-शहरी पृष्ठभूमि के प्रधानमंत्री हुए हैं, मगर वे दिल्ली दरबार के दबदबे में आ गए या उसमें घुलमिल गए. मोदी ने कभी अपने उभार के लिए 'लुटियन दिल्ली' के कर्जदार नहीं रहे. इसलिए हम उनके क्षेत्रीय, नीतियों में सरकारी हस्तक्षेप और कर्मचारियों के मामले में रवैए एक ताजगी है. मनोहर पर्रीकर जैसे राज्यों के नेताओं को आगे लाया गया. दूसरा पहलू निजी निष्ठा की उम्मीद है. मोदी ने अपने कामकाज की नेकनियती से रिकॉर्ड स्थापित किया. उनके परिवार के लोगों का मध्यवर्गीय जीवन इसका सबूत है.[13]

परिणाम

उम्मीदों को असलियत में बदलने के लिए मोदी ने नीतियों पर रवैया बदल दिया. सबसे ज्यादा तो यह दिखता है कि शार्ट-कट के बदले प्रक्रिया और अमल पर जोर है. चाहे वह जन धन हो, स्वच्छता या बिजली कनेक्शन, हर योजना पर सुविचारित पहल की गई और परियोजना की तरह अमल किया गया. टाइमलाइन तय की और फायदे पहचाने गए और उसे साकार किया गया. हर का एक पैमाना था-45 करोड़ जन धन खाते ही एक मिसाल हैं.

मोदी ने नीतियों के निर्माण में दकियानूसी या अहं-केंद्रीत बातों को दरकिनार किया. आधार बढ़ा और जीएसटी पर अमल हुआ. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, घरेलू आलोचनाओं के बावजूद, मोदी ने विरासत के बोझ से प्रभावित हुए बगैर पड़ोसियों की ओर हाथ बढ़ाया. वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी धमक में नहीं आए, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप को हर्ले-डेविडसन की लॉबिइंग करते वक्त एहसास हुआ. मोदी बदलाव में सहज दिखते हैं. अक्षय ऊर्जा पर जोर, योजना आयोग की जगह नीति आयोग या स्टार्ट अप, हर मामला यही बताता है कि विकास की तेज छलांग के लिए कुछ मिटाना जरूरी है. दुसरों से सीखने के लिए भी खुलापन है. रक्षात्मक मुद्रा अपनाने या महज तारीफ बटोरने के बदले भारत में दुनिया की बेहतरीन प्रथाओं को अपनाने की भूख है. मोदी के आत्म-विश्वास के तहत भारत का उत्थान नीतियों के मामले में तीसरे चरण में पहुंच गया है.

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET)

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 6, June 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1106137|

मोदी की कल्याणकारी नीतियों के प्रति रवैया महात्मा गांधी के सर्वोदय से प्रभावित है. कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है-जो इलेक्टॉनिक माध्यमों के जरिए हो, जाति, धर्म, क्षेत्र के प्रति 'अंधा' हो और दलालों से मुक्त हो. प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण, राशन वितरण, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच हो, सभी टेक्नोलॉजी के जरिए है और बिचालियों की भूमिका कम करते हैं. यहां तग कि वापस लिए गए कृषि विधेयक भी किसानों को विकल्प मुहैया कराने और बिचौलियों से छुटकारा दिलाने के लिए था. सबका प्रयास पर जोर दिया गया. हजारों परिवारों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी. 'भरोसा' जगाना कल्याण कार्यक्रमों से ज्यादा जरूरी है.

मोदी लोगों और उद्यमों के लिए अवसर पैदा करने का माहौल बना रहे हैं, ताकि वे कामयाब हों और दुनिया में चैंपियन बनें. स्कील इंडिया और स्टार्ट अप इंडिया जैसी पहल से देश के युवाओं का मानस बदला है. सरकारी नौकरियों की तरफ देखने के बदले, देश में उद्यमी संस्कृति फल-फूल रही है, जिससे रोजगार पैदा होता है. महामारी के दौरान शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान भारतीय कारोबार को पटरी पर लौटाने और भविष्य में प्रगति की राह पर ले गया.उत्पादन केंद्रीत प्रोत्साहन योजना से आत्मनिर्भर भारत देश में उत्पादन क्षमता की संभावनाएं खोलेगा. आश्चर्य नहीं कि 2021 में 40 से ज्यादा यूनिकॉर्न तैयार हुए.

मोदी के आठ साल में भारत ऐसे देश के रूप में उभरा है, जिसमें खुद के लिए ज्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं, और उम्मीदों पर खरा उतरने की क्षमता में भरोसा है. यह मुश्किल राजनैतिक चुनौती है, क्योंकि देश के लोग ज्यादा देर तक खैरात और लुभावने नारे से खुश नहीं रहेंगे. वे बेहतर, टिकाऊ भविष्य चाहेंगे.[14]

निष्कर्ष

अग्निपथ एंट्री स्कीम के तहत सैनिकों को अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा, जिसके बाद रक्षा बलों के पास उनमें से कुछ को सेवा में रखने का विकल्प होगा. इस स्कीम के तहत देश की तीनों सेनाओं- थल सेना, वायु सेना और नौसेना में नए रूप में प्रवेश लेने का अवसर मिलेगा.

सशस्त्र बलों में भर्ती की कोशिशों में जुटे युवाओं के लिए सरकार ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है. खबर है कि बदलाव के बाद नई व्यवस्था के तहत जवानों को चार साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा. यह अवधि खत्म होने के बाद सरकार इन सैनिकों को बड़ी राशि देने का भी फैसला किया है. साथ ही इनमें से करीब 25 फीसदी को सेवा में दोबारा एंट्री मिल सकती है. हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है.

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 6, June 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1106137|

आपको बता दें कि इस योजना के तहत सेना में युवा कम समय के लिए भर्ती हो सकेंगे. योजना को "अग्निपथ" स्कीम नाम दिया गया है. इस योजना के तहत युवा चार साल के लिए सेना में शामिल हो सकते हैं और देश के लिए सेवा दे सकते है. चार साल बाद सेवा से जवान मुक्त कर दिए जाएंगे. माना जा रहा है कि पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके जरिए सेना में शामिल हो रहे जवानों की औसत उम्र कम करने का प्रयास करना रहेगा और रक्षा बलों के खर्चे में भी कमी लाई जाएगी.

अग्निपथ एंट्री स्कीम के तहत सैनिकों को अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा, जिसके बाद रक्षा बलों के पास उनमें से कुछ को सेवा में रखने का विकल्प होगा. इस स्कीम के तहत देश की तीनों सेनाओं- थल सेना, वायु सेना और नौसेना में नए रूप में प्रवेश लेने का अवसर मिलेगा. इस योजना के तहत तीन-चार साल के अंत में, अधिकांश सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें आगे के रोजगार के अवसरों के लिए सशस्त्र बलों से सहायता मिलेगी.

अग्निवीरों के बीच से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को सेना में रखा जाएगा और बाकी को नागरिक नौकरियों के लिए छोड़ने का विकल्प मिलेगा. सैन्य प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी पर रखने के लिए कॉरपोरेट घराने अभी से सरकार के संपर्क में हैं. रिकॉर्ड के मुताबिक वर्तमान में रक्षा बलों में 1.25 लाख रिक्तियां उपलब्ध हैं.[15]

संदर्भ

1. "राष्ट्रपति ने श्री नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया". पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार. 20मई 2014. मूल से 21 मई 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 21 मई 2014. |date= में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद)
2. ↑ "Narendra Modi appointed Prime Minister, swearing in on May 26". Times of India. 20 मई 2014. मूल से 2 अप्रैल 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 21 मई 2014.
3. ↑ "PM Modi turns 69: A timeline of his political career". Deccan Herald (अंग्रेज़ी में). 2019-09-17. मूल से 15 जनवरी 2021 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2021-01-20.
4. ↑ "संग्रहीत प्रति" (PDF). मूल से 13 अप्रैल 2014 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 11 अप्रैल 2014.
5. ↑ "Live Latest News Headlines at newkerala.com Daily News". www.newkerala.com. मूल से 2014-03-15 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2021-01-20.
6. ↑ Marino, Andy (2014-04-06). Narendra Modi: A political Biography (अंग्रेज़ी में). Harper Collins. पृ° 24. आई°ऍस°बी°ऍन° 978-93-5136-218-0.
7. ↑ Shekhar, Himanshu (1901). Management Guru Narendra Modi (अंग्रेज़ी में). Diamond Pocket Books Pvt Ltd. पपृ° 64. आई°ऍस°बी°ऍन° 978-81-288-2803-4.
8. ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 4 अप्रैल 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 मई 2018.
9. ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 20 दिसंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 मई 2018.
10. ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 12 मार्च 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 मई 2018.
11. ↑ "गूगल सर्च में भी नरेंद्र मोदी पड़े राहुल गांधी पर भारी". दैनिक जागरण. मूल से 9 अक्तूबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 9 अक्टूबर 2013.
12. ↑ "Vote Now: Who Should Be TIME's Person of the Year?". टाइम. मूल से 28 नवंबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 नवम्बर 2013.
13. ↑ "नरेंद्र मोद□ न□ अहमदाबाद क□ रैल□ मे□ सुनाई कवित□". नवभारतटाइम्स.कॉम. 20 फ़रवर□ 2014. मूल स□ 12 मई 2014 क□ पुरालेखित. अभिगमन तिथ□ 10 मई 2014.
14. ↑ "कविता के जरिए नरेंद्र मोदी ने बयां किया दर्द-ए-दिल". आज तक. 27 अप्रैल 2014. मूल से 12 मई 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 10 मई 2014.
15. ↑ "Partywise Trends & Result". मूल से 23 फ़रवरी 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 मई 2014.

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor

Impact Factor: 8.118

doi cross ref

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर NISCAIR

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

9940 572 462 6381 907 438 ijirset@gmail.com

Scan to save the contact details